

विचार-प्रवाह...जबर्दस्त
जीत से रास्ता खुलाP3 AGE
UBLICATION

मौसम

अधिकतम तूफान 17.0° ग्रेड
17.0° 7.0°

देहरादून, बृहस्पतिवार, 19 दिसंबर 2019

प्रेज़ श्री



41558.57

2

वैज्ञानिक लेखों का बड़ा प्रकाशक है भारत

7

रोहित शर्मा की दमदार पारी

निर्भया की मां का फूटा गुस्सा

7 जनवरी तक का समय दोषियों को कोर्ट द्वारा मिला, जिससे निर्भया की मां काफी निराश दिखी। निर्भया की मां ने कहा, एक साल से मैं पटियाला हाउस कोर्ट के चक्कर लगा रही हूं। आज फिर मुझे 7 जनवरी की तारीख दी गई है। यहां तो सब अधिकार मुजरिमों के ही हैं, हमारा तो कई अधिकार नहीं हैं। हमारे बचील की बात कोर्ट ने नहीं सुनी। कोर्ट ने भी उनके ही बचीलों की बात सुनी। वहीं सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटिशन खारिज होने पर निर्भया के पिता ने कहा, 7 साल से हम न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच-समझकर फैसला दिया है। फैसले का स्वागत करते हुए निर्भया की मां ने कहा, शैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हूं। हम न्याय के एक कदम और आगे बढ़े हैं। न्याय का इंतजार सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है।

संक्षिप्त समाचार

दम है तो दुष्कर्म पर बोलिएः प्रियंका गांधी

एंजेसी (वेब वार्ता न्यूज़)

रांची। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनौती देती हूं कि सीएनटी-एसपीटी पर बोलिए, दुष्कर्म पर बोलिए, गायब रोजगार पर बोलिए। बीते दिन झारखण्ड की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कांग्रेस को दी गई चुनौती का जवाब देते हुए प्रियंका ने कहा कि आप देश के पीएम हैं या बंटवारे के प्रधानमंत्री हैं, इस पर बोलिए।

इंटरनेट बैन, मऊ में 600 के खिलाफ एफआईआर दर्ज

एंजेसी (वेब वार्ता न्यूज़)

आजमगढ़। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए यूपी में भी इंटरनेट बैन कर दिया गया है। नागरिकता कानून के विरोध में जगह-जगह आरोजक तत्वों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से साशाल मीडिया पर फेलाए जा रही अफवाहों के चलते आजमगढ़ एसपी और डीएम ने बुधवार दोपहर 1 बजे से इंटरनेट सेवाएं बाधित करने की घोषणा की है।

■ क्योरेटिव पिटिशन के बाद दया याचिका का भी विकल्प

एंजेसी (वेब वार्ता न्यूज़)

नई दिल्ली। निर्भया के गुनहगारों फांसी के फंदे के बीच की दूरी और कम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दोषी अक्षय की रिव्यू पिटिशन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साथ में यह कहा कि दोषी तय समय में दया याचिका के विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि, रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों को डेथ वॉरंट जारी करने को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दोषियों को नोटिस जारी किया। डेथ वॉरंट को लेकर अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर दोषियों को नोटिस जारी कर उनसे पूछे कि क्या वे दया याचिका दाखिल करना चाहते हैं। कोर्ट ने निर्भया की मां से कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है। हमें मालम है कि किसी की मौत हुई है लेकिन यहां किसी अन्य के अधिकार की भी बात है।



पटिलाया हाउस कोर्ट ने दोषियों के डेथ वॉरंट पर फैसला 7 जनवरी तक के लिए टाला

द्रायल कोर्ट में डेथ वॉरंट पर सुनवाई टली

सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन खारिज होने के कुछ ही घंटे बाद पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों को डेथ वॉरंट जारी करने को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दोषियों को नोटिस जारी किया। डेथ वॉरंट को लेकर अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर दोषियों को नोटिस जारी कर उनसे पूछे कि क्या वे दया याचिका दाखिल करना चाहते हैं। कोर्ट ने निर्भया की मां से कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है। हमें मालम है कि किसी की मौत हुई है लेकिन यहां किसी अन्य के अधिकार की भी बात है।

दिया और अगली सुनवाई 7 जनवरी के लिए तय कर दी। आइए समझते हैं कि इस केस में अब आगे क्या हो सकता है।

अब आगे क्या-क्या विकल्प

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद द्रायल कोर्ट (पटियाला हाउस कोर्ट) में दोषियों के डेथ वॉरंट पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोषियों को नोटिस

के लिए एक हप्ते का समय दिया जा सकता है।

अक्षय के मामले में रिव्यू का

निपटारा हो चुका है इस तरह

अभी उसे दया याचिका दाखिल

करने की मोहलत मिले गी।

राष्ट्रपति के पास एक और दोषी

विनय की दया याचिका लंबित

है। दया याचिका खारिज होने के

बाद ही फांसी होगी।

एपी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले (रिव्यू पर नहीं) के बाद नए तथ्य सामने आए हैं कि निर्भया के दोस्त ने पैसे लेकर मीडिया को कहानियां बताईं। उन्होंने कहा कि नए तथ्यों के आने के बाद नए सिरे से केस को सुना जाना चाहिए।

बचाव पक्ष के बचील का दावा- अभी भी फांसी से बचने की उम्मीद

निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद अब फांसी से बचने के लिए चारों दोषियों की उम्मीद उन 17 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के रुख पर टिक गई है, जिसमें कोर्ट ने फांसी को उम्रकैद में बदल दिया था। रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद दोषियों के बचील एपी सिंह ने कहा कि वह आज या कल में क्योरेटिव पिटिशन दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने 2017 के बाद के उन सभी 17 मामलों की लिस्ट रखेंगे, जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था।

बंगाल में लागू नहीं करने दुंगी सीसीए

एंजेसी (वेब वार्ता न्यूज़)

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तुण्डमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को कोलकाता में एक जनसभा किए रहे टाटा संस के एग्जिक्युटिव चेयरमैन नियुक्त किए जाएं। साथ ही, उसने एन. चंद्रशेखरन के इस पद पर नियुक्ति को गैरकानी बताया। हालांकि, न्यायाधिकरण ने कहा कि बहाती आदेश चार सप्ताह बाद अमल में आएगा। टाटा संस को अपील करने के लिए यह समय दिया गया है। एनसीएलएटी के दो सदस्यीय बैंच ने यह फैसला सुनाया है। एनसीएलएटी में यह याचिका मिस्त्री और दो इन्वेस्टिमेंट फर्म की तरफ से दाखिल की गई थी।

ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, नागरिकता कानून और एनआरसी को वापस ले लीजिए वरना मैं देखती हूं कि आप इसे यहां कैसे लागू करते हैं। बीजेपी पूरे देश

को हिरासत केन्द्र में बदलना चाहती है लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अमित शाह का कहना है कि आधार कार्ड (नागरिकता का) सबूत नहीं है, फिर आप इसके साथ सब कुछ क्यों जोड़ रहे हैं?

ममता बनर्जी को रैली का तीसरा दिन नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हावड़ा में देखती हूं कि आप इसे यहां कैसे लागू करते हैं। बीजेपी पूरे देश

रही है। आज उनकी नो सीएए ने एनआरसी रैली का तीसरा दिन लागू करने की नोटिस जारी की जाए। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बुधवार को भी प्रदर्शन जारी रहा, इस दौरान हिंसा की कोई खबर नहीं है।

ममता बनर्जी ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ जारी कर दिया है। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ बुधवार को भी प्रदर्शन जारी रहा, इस दौरान हिंसा की कोई खबर नहीं है। मैं अमित शाह से यह सुनिश्चित करने की गुजारिश करती हूं कि देश संशोधित नागरिकता कानून की आग में ना जाए।

ममता बनर्जी ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शनों पर कहा, मैं केन्द्रीय गृह मंत्री से देश का ध्यान रखने और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने की अपील करूंगी। आपका काम आग बुझाना है। मैं अमित शाह से यह सुनिश्चित करने की गुजारिश करती हूं कि देश संशोधित नागरिकता कानून की आग में ना जाए।

जिसे दंगों से फायदा, वही करवाता है